



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226342  
CG-DL-E-01042021-226342

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 194]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

**सा.का.नि. 245(अ).**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्वारा, समझौता आयोग (आयकर तथा धन कर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2015 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को समझौता आयोग (आयकर तथा धन कर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 1 फरवरी, 2021 को लागू किया जाना माना जाएगा।

2. समझौता आयोग (आयकर तथा धन कर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2015 में, नियम 7 में द्वितीय परंतुक के पश्चात् तथा टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित परंतुक को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते यह भी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ठीक पहले इस प्रकार धारित पद को उस तारीख को अथवा से उस पद पर नहीं रहेंगे और उनके पद समापन की समयपूर्व समाप्ति के लिए उन्हें प्रतिकर का दावा करने का हक होगा जो तीन माह के वेतन और भत्तों से अधिक नहीं होगा।”

[फा. सं. क्यू-21013/1/2021-एएआर]

अरविंद सरन, निदेशक

**टिप्पणी:** मुख्य नियमों को सा.का.नि. 235(अ.) दिनांक 27.03.2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रकशित किया गया था।

**स्पष्टीकरण ज्ञापन:** वित्त विधेयक 2021 के खंड 56 के अनुसरण में, 1 फरवरी, 2021 से समझौता आयोग (आयकर तथा धन कर) (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2021 को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जा रहा है जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245ख के तहत एक परंतुक को इस आशय से अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है कि आयकर समझौता आयोग फरवरी, 2021 के प्रथम दिवस को और उसके बाद कार्य नहीं करेगा। अतएव, यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

**G.S.R. 245 (E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Settlement Commission (Income-tax and Wealth-tax) (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 2015 namely: -

**1. Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Settlement Commission (Income-tax and Wealth-tax) (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> February, 2021.

**2.** In the Settlement Commission (Income-tax and Wealth-tax) (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 2015, in rule 7, after second proviso and before Note, the following Proviso shall be inserted namely: -

“Provided also that any person appointed as Chairman, Vice-Chairman or Member holding office as such immediately before the date to be notified by the Central Government in this behalf, shall on and from such date, cease to hold such office, and they shall be entitled to claim compensation not exceeding three months' pay and allowances for the premature termination of term of their office”.

[F. No. Q-21013/1/2021-AAR]

ARVIND SARAN, Director

**Note:** The Principal Rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 30th March, 2015 vide G.S.R. 235(E), dated 27.03.2015.

**Explanatory Memorandum:** The Settlement Commission (Income-tax and Wealth-tax) (Recruitment and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2021 is being given retrospective effect from the 1st February, 2021 in pursuance of clause 56 of Finance Bill, 2021 proposing to insert a proviso under section 245B of the Income-tax Act, 1961 to the effect that Settlement Commission shall cease to operate on or after the 1st day of February, 2021. Therefore, it is certified that no person's interest will be adversely affected by this notification.